Date - 9 April 2022

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग

- हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने चिकित्सकों को चिकित्सा पद्धति के लिए पंजीकृत करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- इसका उद्देश्य भारत में डॉक्टरों की पंजीकरण प्रक्रिया में एकरूपता लाना है।
- इससे पहले, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग (डीओपी) ने चिकित्सा उपकरणों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2022 के मसौदे के लिए एक दृष्टिकोण पत्र जारी किया था।

एनएमसी द्वारा प्रस्तावित चिकित्सा पंजीकरण के लिए मसौदा दिशानिर्देश:

यूनिक ID:

- ये दिशा-निर्देश एक गतिशील राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर बनाने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं, जिसमें प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट आईडी दी जाती है, जिसके पास एनईईटी और अन्य पेशेवर योग्यताएं हैं।

विदेशी डॉक्टरों को अनुमति :

- यह उन विदेशी डॉक्टरों के लिए पंजीकरण सुविधा भी प्रदान करता है जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, फेलोशिप, नैदानिक अनुसंधान, या स्वैच्छिक नैदानिक सेवाओं के अध्ययन के लिए भारत आना चाहते हैं।

राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NExT):

Yojna IAS

- मसौदे में कहा गया है कि भारतीय मेडिकल स्नातक किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री पूरी करने, अपनी साल भर की अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी करने और नेशनल एग्जिट टेस्ट (एनईएक्सटी) पास करने के बाद नेशनल मेडिकल रजिस्टर में पंजीकरण के लिए पात्र हैं।
- एनईएक्सटी न केवल दोनों के लिए समान अवसर प्रदान करेगा, यह एनईईटी-पीजी के बजाय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए एक योग्यता परीक्षा के रूप में भी कार्य करेगा, जिसके लिए उम्मीदवारों को वर्तमान में उपस्थित होना आवश्यक है।
- दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि जब तक NExT को शामिल नहीं किया जाता, मौजूदा प्रक्रियाएं जारी रहेंगी।
- सरकार से वर्ष 2024 से NExT आयोजित करने की उम्मीद है।
- राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में भारत भर में विभिन्न राज्य चिकित्सा परिषदों के साथ पंजीकृत डॉक्टरों की सूची है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी):

- भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) की स्थापना वर्ष 1934 में भारतीय चिकित्सा परिषद (आईएमसी) अधिनियम, 1933 के तहत की गई थी, जिसका मुख्य कार्य चिकित्सा क्षेत्र में और भारत और विदेशों में उच्च योग्यता के एक समान मानक स्थापित करना
- वर्ष 2018 में, सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) को भंग कर दिया और नीति आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- अब भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई), 1956 को निरस्त कर दिया गया है और 8 अगस्त, 2019 को लागू होने वाली गजट अधिसूचना के बाद इसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम के रूप में बदल दिया गया है।
- परिवर्तन का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाना है और विशेष रूप से भ्रष्टाचार और अन्य समस्याओं से भ्रष्ट एमसीआई को बदलना है।
- एनएमसी चिकित्सा शिक्षा में देश के सर्वोच्च नियामक के रूप में कार्य करेगा।

इसके लिए चार अलग-अलग स्वायत्त बोर्ड होंगे:

- स्नातक चिकित्सा शिक्षा।
- स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा।
- चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग।
- नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण।

Yojna IAS

ईओएस-02 उपग्रह

- हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा जानकारी साझा की गई है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह-02 को वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में लॉन्च किया जाएगा।
- महामारी और परिणामस्वरूप लॉकडाउन के कारण लॉन्च में देरी हुई।
- इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह (EOS)-04 और दो छोटे उपग्रहों (INSPIREsat-1 और INS-2TD) को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान-C52 रॉकेट द्वारा वांछित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था।

ईओएस-02 उपग्रह:

- EOS-02 कृषि, वानिकी, भूविज्ञान, जल विज्ञान, लघु विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रतिक्रिया पहियों आदि सहित विभिन्न नई प्रौद्योगिकियों के लिए एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह है और जो SSLV (लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान) -1 के लिए पेलोड है।
- एसएसएलवी सबसे छोटा वाहन है जिसका वजन मात्र 110 टन है। इसे एकीकृत होने में केवल 72 घंटे लगेंगे, जबकि एक प्रक्षेपण यान को अभी भी 70 दिन लगते हैं।
- इसका उद्देश्य छोटे उपग्रहों को छोटे उपग्रहों के लिए विकासशील देशों, विश्वविद्यालयों और निजी निगमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हाल के वर्षों में उभरी निम्न-पृथ्वी कक्षाओं में लॉन्च करने के लिए एक बाजार प्रदान करना है।

ईओएस श्रृंखला में अन्य उपग्रह:

ईओएस-01:

- कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता के लिए एक 'अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट' (ईओएस) ।

ईओएस-03:

- भूस्थिर कक्षा में पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसमें निकट वास्तविक समय इमेजिंग, प्राकृतिक आपदाओं की तीव्र निगरानी, कृषि, वानिकी आदि से संबंधित उपकरण शामिल हैं।

ईओएस-04:

- रडार इमेजिंग उपग्रह, जिसका उद्देश्य कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान और बाढ़ मानचित्रण जैसे अनुप्रयोगों के लिए सभी मौसम की स्थिति में उच्च गुणवत्ता वाली छवियां प्रदान करना है।

ईओएस-05:

Yojna IAS

- भूस्थिर कक्षा में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह।

ईओएस-06:

- समुद्र से संबंधित सेवाओं, संभावित मात्स्यिकी क्षेत्र और समुद्र की स्थिति के पूर्वानुमान से संबंधित अनुप्रयोगों के लिए 'पृथ्वी अवलोकन उपग्रह'।

'पृथ्वी अवलोकन उपग्रह' क्या हैं?

- 'पृथ्वी अवलोकन उपग्रह' सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी से लैस उपग्रह हैं। पृथ्वी अवलोकन से तात्पर्य पृथ्वी की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रणालियों के बारे में जानकारी के संग्रह से है।
- कई पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को सूर्य-समकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है।
- इसरो द्वारा लॉन्च किए गए अन्य पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों में रिसोर्ससैट-2, 2ए, कार्टोसैट-1, 2, 2ए, 2बी, रिसैट-1 और 2, ओशनसैट-2, मेघा-ट्रॉपिक्स, सरल और स्कैटसैट-1, इन्सैट-3डीआर, 3डी शामिल हैं।

Yojna IAS

टूर ऑफ ड्यूटी

- सैन्य मामलों का विभाग टूर ऑफ ड्यूटी (टीओडी) योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।
- इस योजना के तहत युवाओं को केवल तीन साल के लिए सैनिकों के रूप में भर्ती किया जाएगा।
- यह बढ़ते वेतन और पेंशन बिलों को रोकने की तत्काल आवश्यकता की पृष्ठभूमि में सैन्य आधुनिकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की पृष्ठभूमि में किया जा रहा है।

'टूर ऑफ ड्यूटी' (टीओडी) योजना

- पृष्ठभूमि: इस योजना को दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा था।
- परिचय: इसमें तीन साल की निश्चित अवधि के लिए सैनिकों की भर्ती करना शामिल है, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा।
- यह एक स्वैच्छिक संघ होगा।
- इसे अग्निपथ प्रवेश योजना के नाम से भी जाना जाता है।
- यह योजना उन युवाओं के लिए है जो 'रक्षा सेवाओं को अपना स्थायी पेशा नहीं बनाना चाहते, लेकिन फिर भी सैन्य पेशेवरता के रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं'।
- सैनिकों को लाभ: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सहित कुछ सरकारी नौकरियों में भर्ती में प्राथमिकता के साथ सैनिकों को मौद्रिक भुगतान दिया जाएगा।
- इसके अलावा निजी क्षेत्र के तहत भी इस योजना के तहत लगे लोगों को प्राथमिकता देने पर विचार किया जा रहा है.
- सरकार को लाभ: 'टूर ऑफ ड्यूटी' योजना से न केवल सैन्य कर्मियों की कमी के मुद्दे को हल करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे वेतन वृद्धि और पेंशन का बोझ भी कम होगा।
- मूल टीओडी प्रस्ताव के अनुसार, पेंशन और अन्य लाभों के साथ, 17 साल की सेवा पूरी करने के बाद एक जवान के काम की लागत में "संभावित जीवन-काल बचत", एक टीओडी जवान की तुलना में 5 करोड़ रुपये होगी।
- वेतन और ग्रेच्युटी भुगतान में बचाए गए संचयी धन का उपयोग आवश्यक सैन्य आधुनिकीकरण के लिए किया जा सकता है।

Yojna IAS

Swadeep Kumar